CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

[Conference Special-NTMAE-24]

शिक्षा की वैश्विक चुनौतियाँ

मनोज कुमार
शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
डॉ. सीमा दायमा
प्राचार्या (बी.एस.सी–बी.एड.) श्री बालाजी पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर
Email- kumarmanoj381f@gmail.com, Mobile- 7568278882

First draft received: 02.05.2024, Reviewed: 10.05.2024, Final proof received: 19.06.2024, Accepted: 24.06.2024

सारांश

प्रस्तुत प्रपत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। अगर हम हमारें देश की शिक्षा प्रणाली की बात करे तो भारतीय शिक्षा प्रणाली ने कई सुधारों और परिवर्तनों के साथ एक लंबा सफर तय किया है। अनेक संशोधनों के बावजूद, हम अभी भी विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली बनने से कोसों दूर हैं। आजादी के 77 साल बाद भी, सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक विकासशील देश के रूप में, हमें 21वीं सदी की वैश्विक शिक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।[1]

हाल के दशकों में देश के आर्थिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में ढाँचागत एवं नीतिगत स्तर पर काफी प्रगति हुई है। फलस्वरुप देश की विकास दर तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधारों को गति प्रदान की है, लेकिन इन परिवर्तनों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं को दूर नहीं किया है। प्रस्तुत प्रपत्र में हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विश्व में स्थिति, विद्यमान समस्याओं एवं संभावित समाधानों की चर्चा करेंगे।

मुख्य-शब्द : *शिक्षा, वैश्विक, चुनोतियाँ इत्यादि.*

प्रस्तावना

शिक्षा के स्तर में सुधार करना आज एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है। इसी संदर्भ में वैश्विक स्तर पर 2015 में स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य 2023 के अंतर्गत चोथे लक्ष्य के अन्तर्गत सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने की हर राष्ट्र से अपेक्षा है। भारत की नई शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि शिक्षा द्वारा उच्च स्तर के तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए।

21वीं शताब्दी के भारत को वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है। इसके लिए देश को एक प्रत्यारोपित शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर अग्रसर होगा जिसकी जडे गहराई तक भारत की मिट्टी से पोषण पा रही हो और जो नए ज्ञान को ग्रहण कर प्रगति के मार्ग पर चलने को कटिबद्ध हो इसकी सफलता से ही बल शिक्षा का वैश्विक आकर्षण केंद्र बन सकेगा।[3]

शिक्षा की वैश्विक चुनौतियाँ

भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल और 260 मिलियन से अधिक छात्र हैं। देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा के कई स्तरों में विभाजित है। हालांकि, देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई चुनौतियाँ हैं, जो विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डालती हैं, जिनका उल्लेख निम्न है –

उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की अपर्याप्त आपूर्ति है

कम गुणवत्ता वाली शिक्षण प्रक्रिया एक बड़ी समस्या है और कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह बदतर होती जा रही है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में, प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत 2000 में 84 प्रतिशत से गिरकर 2019 में 69 प्रतिशत हो गया। विश्व स्तर पर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों के शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी है।[4]

निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा

''भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक शिक्षा की निम्न गुणवत्ता है। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद, कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अभी भी प्रशिक्षित शिक्षकों और आधुनिक पाठ्यक्रम का अभाव है। प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट की बजाय रटने पर जोर दिया जाता है जिससे छात्रों का ज्ञान वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में लागू नहीं हो पाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60: भारतीय बच्चे अपनी उम्र के अनुसार अपेक्षित स्तर पर नहीं पढ़ सकते हैं, और 70: बुनियादी अंकगणितीय कार्यों में संघर्ष करते हैं। वहीं एनसीईआरटी के अध्ययन से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में केवल 55 प्रतिशत और निजी स्कूलों में 71 प्रतिशत शिक्षक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं।

बुनियादी ढांचे की कमी

भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों में से एक स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। भारत में कई स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, अस्वच्छता, शौचालय और खेल के मैदान सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसका छात्रों की उपस्थिति और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण छात्र अक्सर स्कूल नहीं जाते हैं। 2016 की वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, केवल 68.7 प्रतिशत स्कूलों में योग्य शौचालय की सुविधा थी और लगभग 3.5 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं थी।

छात्र–शिक्षक अनुपात

छात्र–शिक्षक अनुपात स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को दर्शाता है। यूनेस्को की भारत के लिए शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, स्कूलों में 11.16 लाख शिक्षण पद खाली हैं। छात्र–शिक्षक अनुपात वित्त वर्ष 2013 से 22 तक सभी

स्तरों पर लगातार बढ़ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षक अपना लगभग 19 प्रतिशत समय शिक्षण में लगाते हैं जबकि उनका बाकी समय गैर–शिक्षण प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत होता है। जबकि सरकारी शिक्षकों को उनके प्रदर्शन की परवाह किए बिना नौकरी की सुरक्षा की आजीवन गारंटी मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ओर से कोई जवाबदेही नहीं होती है।

उच्च–ड्रॉप आउट दरें

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 2021–22 तक कई राज्यों में कक्षा 10 में ड्रॉप आउट दर 20.6 प्रतिशत है। उड़ीसा, बिहार, मेघालय, कर्नाटक, आँध्रप्रदेश, असम राज्यों में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, 6–14 वर्ष की आयु के छात्र अपनी शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि, स्कूल छोड़ने के कई कारक जिम्मेदार हैं जिसमें गरीबी, शौचालयों की कमी, स्कूल की लंबी दूरी, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सांस्कृतिक कारक आदि।

वित्तीय संसाधन की कमी

स्कूलों को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक फंड मुहैया कराती है। 1968 के बाद से प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता है। 2019–20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अब तक भारत ने शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.1 प्रतिशत खर्च किया। इसके अलावा, बीच में भ्रष्ट मध्यस्थों के कारण पूरे फंड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्कूलों तक पहुंच पाता है। धन की उपलब्धता की कमी के कारण स्कूलों की पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी आवश्यकताओं को स्कूलों द्वारा उचित रूप से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है।

शिक्षा की सामर्थ्य और पहुँच

शिक्षा की सामर्थ्य और पहुंच भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। भारत में शिक्षा अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सस्ती नहीं है। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की पहुँच में महत्वपूर्ण असमानता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा लिंग भेदभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें लड़कियां अक्सर समस्याओं का सामना करती हैं।[5]

इसके अलावा निम्न चुनौतियाँ व समस्याएँ है –

- शासन की गुणवत्ता में कमी
- शिक्षा प्रणाली ''समावेशी'' नहीं है
- शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी
- पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी
- स्कूल स्तर के आँकड़ों की अविश्वसनीयता
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि
- अवसंरचना का अभाव
- शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग
- महंगी उच्च शिक्षा
- लैंगिक मुद्दे
- भारतीय बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का समाधान :

- ''सरकार को अधिक लचीले और आधुनिक पाठ्यक्रम के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक कौशल और दक्षताओं पर केंद्रित हो, ताकि समय और बदलती जरूरतों के लिए प्रासंगिक है, पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।
- सरकार को शिक्षा में डिजिटल तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और ई–लर्निंग टूल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और लचीले शिक्षण विकल्प प्राप्त हो सके।
- शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए जाने चाहिए कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित विशिष्ट योग्यताओं और मानकों को पूरा करें।
- भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, योग्य शिक्षकों को नियुक्त करने और आधुनिक शिक्षण विधियों को शुरू किया जा सके। हालांकि, शिक्षा व्यय में वर्ष 1952 से 2014 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13 हो गया। इसके अतिरिक्त, शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सके।
- सभी के लिए सस्ती और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल और विश्वविद्यालय बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है।[6]

समाधान

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।
- सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर शिक्षा की वैश्विक चुनौनियों का समाधान होना नितान्त आवश्यक हैं। बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने एवं देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त किया जाए। अतः हमें अन्य सुधारों के साथ–साथ उचित प्रशासन मानकों, सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन और चेक और बैलेंस की नीति अपनाने की जरूरत है।

सन्दर्भ

1. www.k8school.com
2. www.drishtiias.com
3. www.jansatta.com
4. www.blogs.worldbank.org
5. www.linkedin.com
6. www.linkedin.com